(ख) यदि हां, तो कब तक इसमें परिवर्तन किये जायेंगे और किस तरीके से ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) संविधान में हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कतिपय रक्षोपायों का उपबंध है। सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप शीघ्र, निष्पक्ष और कम खर्चीला न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय प्रशासन की विद्यमान प्रणाली के पुनर्विलोकन की आवश्यकता पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। न्यायिक सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है।

Transportation of Coal by Road by Coal India

*713. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government have allowed Coal India to transport coal by road;

(b) if so, what is the procedure and how many persons or parties have taken advantage of it; and

(c) the total amount of coal meant for transportation by road?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) to (c). Since coal is transported by the consumers, the question of Government allowing Coal India to transport coal by road does not arise. However, a large number of consumers all over the country who are located either close to the coalfields or who are not able to obtain adequate number of railway wagons for transporting coal, obtain their coal requirements by road. In 1980-81, about 25 million tonnes of raw coal was transported from the mines of Coal India and Singareni Collieries Co., Ltd., by road. Coal companies do not maintain any consolidated data regarding the number of consumers to whom coal has been released by road.

Building of Low Cost Cinema Houses in Semi-Urban and rural Areas.

*714. SHRI JAGDISH TYTLER:
SHRI HIRALAL R. PARMAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the National Film Development Corporation is launching a project for promoting the building of low-cost cinema houses in semi urban and rural areas;

(b) if so, the details of this scheme;

(c) the number of cases which have already been approved by it; and

(d) the financial implication thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). The scheme for financing the construction of low-cost cinema houses in rural, semi-urban and urban areas was launched by the erstwhile Film Finance Corporation during 1979. The Corporation was amalgamated with the National Film Development Corporation in April, 1980 and the scheme is now being operated by the latter company. A statement giving broad details of the Scheme is laid on the Table of the House

(c) and (d): The Corporation has so far sanctioned loans in 17 cases for a total amount of Rs. 85.76 lakhs.

Statement

Broad Details of the Scheme for Financing construction of theatres by National Film Development Corporation.

I. The theatres will be functional and economical.

II. The Corporation finances construction of theatres on the following scales:—

(a) For theatres in rural areas, loan upto a maximum of Rs. 1 lakh;

(b) For theatres in semi-urban areas, loan upto a maximum of Rs. 3 lakhs.

(c) For theatres in urban areas, loan of 50 per cent of the total cost upto a maximum of Rs. 7.5 lakhs.

III. Repayment will be in 60 equal instalments commencing from 30 days after the opening of the theatre or within the following time limits, whichever is earlier:—

(a) For theatres in rural areas, 8 months from the date of release of first instalment;

(b) For theatres in urban areas, 11 months from the date of release of first instalment;

(c) For theatres in urban areas, 14 months from the date of release of first instalment.

IV. Interest on these loans is 12½ p.a. with rebate of 1 per cent for payment on due dates, and a further rebate of 1 per cent payment within half of the stipulated period.

V. Theatres financed under these schemes shall be available on 50:50 percentages sharing basis for screening NFDC financed/sponsored films.

हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे मेले के लिए प्रचार

*795. **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे एशिया में प्रसिद्ध मेले का प्रचार करने वाले उनके मंत्रालय के यूनिटों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में अगले वर्ष सम्भावित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या फिल्म डिविजन का विदेशों में प्रदर्शन हेतु हाथियों के मेले के आधार पर एक रंगीन विशेष फिल्म बनाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों का अपने कवरेज / प्रचार कार्यक्रमों में देश के विभिन्न मेलों और त्यौहारों का उपयुक्त रूप से उपयोग करने का सतत प्रयास रहता है। पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व सन्ध्या पर हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) में लगे इस मेले को उपयुक्त कार्यक्रम के रूपों के माध्यम उपयुक्त प्रचार से कवरेज दिया गया था। इस अवसर पर विभिन्न माध्यम एककों द्वारा दिए गए कवरेज आयोजित किए गए कार्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) इस अवस्था पर माध्यम एककों द्वारा कोई विशिष्ट योजना सोची नहीं गई है। तथापि माध्यम एकक अपनी सामान्य गतिविधियों के अंग के रुप में इस मेले को उपयुक्त प्रचार/कवरेज देते रहेंगे ।

(ग) फिल्म प्रभाग सोनपुर मेले की झलकियों को 1949 से अपनी न्यूज-रीलों में कवर कर रहा है और उन्हें रिलीज कर रहा है। तथापि यह समझा जाता है कि संभवतया विशेष डाकुमेन्ट्री फिल्म, सादी या रंगीन, का निर्माण रोचक न हो, क्योंकि मेले में भाग लेने वालों की संख्या कम होती जा रही बताई गई है।